

कम मतदान चिन्ता का कारण

कम मतदान वर्तमान लोकसभा चुनाव में चिन्ना का कारण है। यह प्रवृत्ति मतदान के छठे चरण में भी जारी रही। इसका कारण गर्मी या शायद राजनेताओं से निराशा या निष्क्रियता हो। शायद बहुत से मतदाता सोचते हों कि राजनीतिक पार्टियों ने हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की हालत खराब कर दी है। पश्चिम बंगाल एक अपवाद है जहां मतदाता बड़ी संख्या में सामने आए, पर अधिकांश अन्य राज्यों में वे मतदान केन्द्रों पर उतने जोश से नहीं आए। मतदान के छठे चरण में भी स्थिति पहले जैसी रही। पूरे भारत में मतदाता सहभागिता में चिन्नाजनक रूप से कमी आ रही है। हालांकि, यह प्रवृत्ति सभी क्षेत्रों में नहीं है, बंगाल तथा जम्मू कश्मीर उल्लेखनीय अपवाद हैं जहां यह तुलनात्मक रूप से स्थिर है या इसमें वृद्धि हुई है। मतदाताओं की सहभागिता घटने के पीछे के कारण समझना जरूरी है ताकि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के समक्ष अने वाली चुनौतियों को समझा जा सके। इस प्रवृत्ति के कुछ कारण हो सकते हैं। मौसम का बहुत खराब होना, पहले से ही निर्धारित द्युकाव या स्वयं लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही बढ़ती निराश इनमें शामिल हैं। मौसम के बहुत खराब होने से मतदाताओं की संख्या घटी है। छठे चरण के मतदान के समय मौसम बहुत खराब रहा और कई क्षेत्रों में भयानक लू चल रही थी। इससे खासकर वृद्धि व स्वास्थ्य समस्यों से ग्रस्त मतदाता मतदान केन्द्रों तक जाने से होत्तसाहित हो सकते हैं। इस परिघटना का एक कारण यह भी हो सकता है कि मतदाताओं ने किसी खास पक्ष को चुन लिया हो और यह अनुमान लगा कर वे मतदान से विरत रहे हों कि उनका उम्मीदवार हारने वाला है। वास्तव में कमज़ोर उम्मीदवारों के समर्थक निराश हो सकते हैं। उन्होंने

The image shows a close-up of a dark wood plaque. The words "NIRVACHAN SELECTION COMMITTEE" are printed in a large, bold, sans-serif font. Below this, the word "INDIA" is written in a slightly smaller font. Above the main text, the Hindi word "निर्वाचन समिति" is written in Devanagari script. The entire plaque is mounted on a light-colored wooden wall.



लोकसभा चुनाव में एम फैक्टर्स या आयाम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें मीडिया, मनी, महिला, माइक्रोइकोनामी के साथ अब मोदी, मंदिर तथा मंगलसूत्र आयाम भी जुड़ गए हैं।



प्रा. विवक्त सह
(लेखक, राजनीतिक
विश्लेषक हैं)

लोकसभा चुनाव 2024 में अब एक चरण का ही मतदान बाकी है। वर्तमान लोकसभा चुनाव में ऐसे अनेक महत्वपूर्ण आयाम हैं जिनका मतदाताओं पर व्यापक असर पड़त है। उनमें से 11 आयाम प्रमुख हैं जो एम से शुरू होते हैं। इनमें पहला एम मीडिया है समाज की दिशा को दिखाने और समाज को दिशा दिखाने में मीडिया का बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। मीडिया समाज का दर्पण है समय में बदलाव के साथ मीडिया में भी बड़े बदलाव हुए हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ सोशल मीडिया भी कदमताल कर रहा है। समस्त राजनीतिक दल मीडिया का भरपूर उपयोग कर रहे हैं मोबाइल हैंडसेट और इंटरनेट की सुलभता से मीडिया आज हर घर तक पहुंचने में समर्थ है। पल भर में कोई खबर या घटना करोड़ों लोगों तक पहुंच रही है। एक तरफ जहां सरकार मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी उपलब्धियां को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करती है वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार की नाकामियों को जनता तक ले जाती है मीडिया राजनीतिक दलों के लिए प्रमोशन का सबसे उत्तम साधन है। मीडिया के उपयोग से एक पार्टी या नेता की छवि को बेहतर से बेहतरीन किया जा सकता है।



समाजवादी पार्टी, एआइएमआइएम जैसी पार्टियों से बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। मुस्लिम मतदाताओं का बिखराव किसी पार्टी के लिए वरदान तो किसी पार्टी के लिए अधिकारीय सिद्ध होता रही है। वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआइएमआइएम के प्रदेश में चुनाव लड़ने से मुस्लिम मतदाताओं में बिखराव हुआ जिसका नुकसान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हुआ, जबकि इससे बीजेपी को फायदा हुआ। पूर्व के लोकसभा और राज्यों के अनेकों विधानसभा के चुनावों में यह भी देखने को मिला है कि मुस्लिम समुदाय की गोलबंदी की वजह से हिन्दू समुदाय की गोलबंदी हुई जिससे चुनाव में बड़े उलटफेर हुए। मुस्लिम महिला मतदाताओं का रुझान ट्रिपल तलाक पावंदी और महिला सुरक्षा को लेकर हाल के वर्षों में बीजेपी के प्रति सकारात्मक रूप से बदला है जिसका असर चुनावी नीतियों के रूप में जाहिर है। कोई दो राय नहीं है कि धार्मिक दृष्टि से देश के दूसरे सबसे बड़े मुस्लिम समुदाय की इस चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रहगी।

चुनाव के संदर्भ में मार्केटिंग की बढ़ती भूमिका के लिए-बिन मार्केटिंग सब सून कहा जा सकता है। मार्केटिंग टैक्टिक्स का उपयोग करके जनता को अपनी सरकार या पार्टी की तरफ आसानी से आकर्षित किया जा सकता है। बिना अच्छी मार्केटिंग के देश और समाज में पार्टी की वैल्यूएबल बांड-

रोड़ जनता तक पहुंचने के लिए मार्केटिंग का सहारा लेना आवश्यक है। मार्केटिंग का पृथक् कार्य सकारात्मक नीति, नीयत और निवृत्ति को जनता तक पहुंचना है। मार्केटिंग के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही साथ सोशल मीडिया का उपयोग किया जा सकता है। मार्केटिंग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में हो सकती है। एसीटीयां स्वयं के लिए सकारात्मक मार्केटिंग नबकिं विरोधी पार्टीयों के लिए नकारात्मक मार्केटिंग का उपयोग करती हैं। इस चुनाव के दौरान एक और एम फैक्टर उभरकर सामने आया है जिसका असर चुनाव पर होगा वह मंगलसूत्र। ग्रामीण भारत में मंगलसूत्र निवाहिक शिथि को प्रदर्शित करता है। यह दोनों याद रखना चाहिए कि देश की 70 प्रतिशत आबादी गांव में ही निवास करती है। मंगलसूत्र प्रसंग का व्यापक असर इस चुनाव के देखने को मिल सकता है क्योंकि यह निवाहिलाओं से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है।

चुनावी दृष्टिकोण से पिछले 10 वर्षों में देश में मोदी फैक्टर सबसे बड़े फैक्टर के रूप में उभरा है। मोदी फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा और मजबूत फैक्टर है। यह एक ऐसा चुनावी फैक्टर है जो चुनाव के अन्य बड़े फैक्टर्स पर भारी है, इसकी मनदेखी करना माने अपने पैर पर कुल्हाड़ी लगाना है। देश में कई जगहों पर ऐसी स्थिति बन गई है जहां मतदाताओं को स्थानीय उम्मीदवार से कोई मतलब नहीं है बस मोदी फैक्टर की वजह से वे उम्मीदवार को बोट देंगे। मोदी फैक्टर को सपोर्ट करने के लिए

मामीदावर तलाशन का युद्ध जारा है उसके बाद जाब के चुनाव में कोई इसका अपवाह नहीं है। इससे लोगों में 'विश्वास' की 'कमी' तथा 'आत्मविश्वास की कमी' दृढ़ है और राजनेता वर्ग पार्टी बदलने की भी इच्छा है। आजपाए उस बात का ब्रेय दिया जा सकता है कि यह जीवन्त अर्थव्यवस्था के साथ सुशासन वलाती है, पर उस पर अमीर-समर्थक विधायिका छोटे बिजनेसों, किसानों, दूकानदारों व गहरी व ग्रामीण गरीबों तथा धार्मिक संगठनों के बीच अर्थव्यवस्था के आरोप हैं। देश व दुनिया की अर्थव्यवस्था को 'दुनिया की पांचर्वों सब लोगों के लिए बड़ी अर्थव्यवस्था' कहा जा रहा है, जिसके लोग गरीब और बेरोजगार हैं तथा जिनमें बढ़ रही हैं।

कांग्रेस को समावेशी नीतियों का ब्रेय दिया जा सकता है और उसने किसानों की समर्थक एमएसपी का वादा किया है, जिसमें भयानक गुटबाजी है तथा अतिरिक्त उसका प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है। 'आजपाए उसे मुफ्त बिजली व महिलाओं को मुफ्त दिया जाएगा' यही नीति है।

ह, वह अनुभवहान ह तथा दल्ला पर अत्यधिक निर्भर है। शिअद ऐतिहासिक रूप से राज्य-समर्थक दृष्टिकोण अपनाता रहा है, पर पार्टी पर परिवार के नियंत्रण से उसकी छवि खराब हुई है और वह कार्पोरेट-समर्थक है। कम्युनिस्टों को उनकी इमानदारी, प्रतिबद्धता, सेक्युलरवाद और गरीब-समर्थक विचारधारा का श्रेय दिया जा सकता है, पर उनके पास चुनाव लड़ने के लिए संसाधनों की कमी है, वे चुनाव जीतने में अक्षम हैं तथा सरकार में उनकी कोई खास भूमिका नहीं होगी। मतदाता भ्रमित हैं क्योंकि उनको यह विश्वास नहीं है कि कांग्रेस, भाजपा, शिअद या आप को दिया उनका वोट उम्मीदवार को विजय दिलाने के बाद उसी पार्टी में रखेगा और वह दूसरी पार्टी में जा सकता है। उनको यह भी नहीं लगता है कि पार्टियां जो कह रही हैं, वही करेंगी। इसके बावजूद उनको किसी न किसी को चुनाना है। लेकिन यह तो मतदान वाले दिन होगा। वर्तमान समय में स्थिति राजनीतिक पार्टियों के घोषणापत्रों की तरह भ्रामक है—आपका जीवन चर्चा है।

ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਬਹੁਕੋਣੀਯ ਸੁਕਾਲਾ



पार्टियों ने अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर 'मेकओवर' किया है। अनेक लोग मजबूत समझी जाने वाली पार्टियों में चले गए हैं और उन्होंने 'मजबूत' नेताओं को अपने साथ जोड़ा है। यह स्थिति राजनेताओं की इस 'गलत' समझ पर आधारित है कि लोकतंत्र का अर्थ 'बारी-बारी' से शासकों को चुना तथा 'नागरिकों' को अपनी 'प्रजा' समझना है जो उनकी नीतियों पर चलते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र पुनः परिभाषित होकर लोगों की लोगों द्वारा सरकार होती है, पर वह 'लोगों के लिए' नहीं होती है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय बादे करती हैं, पर जीतने के बाद वे अपने बादे पूरे नहीं करती हैं। चुनावों के बाद वे ऐसी नीतियों का पालन करती हैं जो राजनेता वर्ग, निगमों तथा उनके सहायकों को लाभ पहुंचाती हैं। इस प्रकार सत्ता में पहुंचने पर राजनीतिक पार्टियां और लोग असली मुद्दों को छोड़ कर भावनात्मक तथा हाशिये के मुद्दों पर काम करते हैं। इससे लोगों को कुछ हासिल नहीं होता है। इससे राजनीतिक पार्टियां 'फिर्फर्ट' से नहीं हैं, वे सामाजिक दोषों के बढ़ने की वजह से अपने

A large crowd of people, mostly Sikhs, gathered outdoors. Many are wearing turbans and holding various flags, including the Indian national flag and other religious or political flags. The scene suggests a significant public event or protest.

आरक्षण में सेंध

‘कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए 2010 के बाद जारी ओबीसी सर्टिफिकेट को कानून सम्मत न नामते हुए रद्द कर दिया। हसपे देश भर में ओबीसी आरक्षण में सेंध लगाने के प्रयासों पर बहस शुरू हो गई है। भाजपा, माकपा और कांग्रेस के नेताओं ने इसके लिए ममता सरकार को जिम्मेदार बताया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने करीब 77 मुस्लिम जातियों को आरक्षण की श्रेणी में रखते हुए ओबीसी के सर्टिफिकेट जारी किए थे। उच्च न्यायालय ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग एवं पश्चिम बंगाल सरकार की कार्यशैली पर प्रहार करते हुए कहा कि धर्म को बनाया गया है जो कि न्याय संगत नहीं है और संविधान के विरुद्ध है। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। कोलकाता उच्च न्यायालय के फैसले के बाद राजस्थान व अन्य राज्यों में भी ओबीसी में मुस्लिम जातियों को शामिल कर आरक्षण में सेंध लगाने के प्रयासों पर व्यापक प्रतिक्रिया होने की उम्मीद है। ऐसे में केन्द्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि ओबीसी सूची में शामिल गैर-मुस्लिमों को कोई नुकसान न हो और पहले की तरह उनको नौकरियों व शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था निर्वाचित रूप से जारी रहे।

- वॉरेन्द्र कुमार जाटव, दिल्ली

अग्निकांडों से सबक

सेंतीस लोगों की जान लेने राजकोट गेम जोन हादसे में सुरक्षा के इन्तजाम नहीं थे। अभी तक की जांच में संचालकों की घोर लापवाही सामने आई है। राजकोट अग्निकांड पर गुजरात हाईकोर्ट ने स्वतंत्र रूप से संज्ञान लिया है। कोट ने इस हादसे को मानव निर्मित त्रासदी बताते हुए बढ़े शहरों के निगमों के साथ सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली में चाइल्ड केर हॉस्पिटल में आग लगने से कई बच्चे मरे गए। छत्तीसगढ़ के बामेतरा भयानक विस्फेट से कई लोगों के मरे जाने और लापता होने के समाचार हैं। इस गर्मी में मार्च माह से ही लगातार भयानक अग्निकांड हो रहे हैं। विडंबना है कि सरकारें और प्रशासन हर अग्निकांड के बाद सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन और मुआवजा देकर खामोश हो जाते हैं। भविष्य में सार्वजनिक स्थलों, कारखानों, हॉस्पिटलों, आदि को भयानक अग्निकांडों से बचाने के लिए अग्निशमन विभाग के और विस्तार के साथ ही अग्नि-सुरक्षा संबंधी कानूनों को अनिवार्य रूप से कठोरता से लागू किया जाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर नगर निगम, अस्पताल व अन्य सार्वजनिक स्थल बार-बार अग्निशमन विभाग की चेतावनी के बावजूद उपयुक्त कदम नहीं उठाते हैं जिसका खामियाजा जनता भुगतती है।

- सुभाष बुडावन वाला, रतलाम

ऋषि सूनक का फैसला

ऋषि सुनक ने एक साल पहले मध्यावधि चुनाव कराने का फैसला किया है। हालांकि, इस समय उनकी तथा उनकी पार्टी की लोकप्रियता बहुत नीचे चली गई है, पर अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करते हुए उन्होंने यह फैसला किया है। ऋषि सुनक ने ऐलान किया कि उन्होंने राजा चार्ल्स तृतीय से बात कर निचले सदन हाउस ऑफ़ कॉमन्स को भंग करने का आग्रह किया जिसे उन्होंने मान लिया। अब ब्रिटेन में 4 जुलाई को चुनाव होंगे। अनेक कारणों से अपना पदभार संभालने के समय से ही ऋषि सुनक अनेक समस्याओं में घिरे रहे तथा ब्रिटेन को प्रगति के पथ पर ले जाने में सफल नहीं हुए। वर्तमान समय में देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है तथा महांगई चरम पर है। सरकारी क्षेत्र के अनेक विभागों के कामगार अक्सर हड्डाल कर रहे हैं। कंजरवेटिव पार्टी ने ब्रेक्सिट का जो हसीनी सपना नागरिकों को दिखाया था, उसके भयानक परिणाम सामने आए हैं। इसी कारण पिछले सालों में कई प्रधानमंत्री बने, पर उनको जल्द ही बदल दिया गया हालांकि, ऋषि सुनक अपनी पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पर जनमत सर्वेक्षणों के अनुसार अब लेबर व लिबरल पार्टीयों के प्रतिनिधियों के सत्ता में आने की पूरी उम्मीद है।

- जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

इन्वर्टेड ड्यूटी की समरण्या

कोई सामान या मशीन बनाने पर कहीं स्पेयर पार्ट्स को न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर के अनेक देशों में आयात करना पड़ता है। ऐसे आयातित सामान पर टैक्स लगता है जिससे निर्मित वस्तुओं की लागत बढ़ जाती है इसके कारण अनेकानेक निर्मित वस्तुएं बाजार में महंगी हो जाती हैं। ऐसे आयातित माल पर-उल्टा शुल्क, यानी इनवर्टेड इयूटी लगाया जाता है। केंद्र सरकार से अपेक्षा है कि ऐसे सामानों के उत्पादन के लिए जरूरी स्पेयर पार्ट्स का निर्माण यथासंभव देश में ही किया जाए। कांगज, वाशिंग मशीन, सोलर एनर्जी, वाटर प्यूरीफायर आदि वस्तुओं के निर्माता इनके अनेक स्पेयर पार्ट्स आयात करते हैं क्योंकि विदेश में ये कम कीमत पर उपलब्ध होते हैं। ऐसे में यदि इनवर्टेड इयूटी समाप्त की जाए या इसे घटाया जाए तो इसका लाभ सीधे उपभोक्ताओं को मिलेगा। हालांकि, देश को विभिन्न प्रकार के हिस्से-पूर्जे बनाने में आत्मनिर्भर बनाना सर्वोत्तम विकल्प है, पर विनिर्माण की जटिलताओं, निरंतर प्रगति कर रही तकनीकों तथा आवश्यकतानसार क्षमताओं के विस्तार को देखते हुए इनके आयात से पूर्ण मुक्ति बहुत कठिन है।

- दत्तप्रसाद शिरोड़कर, मुंबई

पाठक अपना प्राताक्रिया इ-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com

